असंतुलित विकास से आया आर्थिक संकट

देश में मौजूदा आर्थिक संकट का मूल कारण पिछले एक दशक के दौरान हुआ असंतुलित विकास है, जिसके कारण देश का व्यापार असंतुलन बिड़ना और रुपया कमजोर हो रहा है. साथ ही विनिर्माण क्षेत्र मंदी की गिरफ्त में आ गया है. यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में पिछले 9 वर्षों में देश का विकास किया, यह सही है. लेकिन यह विकास सही तरीके से नहीं हुआ. इसी का दुष्परिणाम आज हमारे सामने है. सरकार ने देश में बिजली की कमी दूर करने कोयला व गैस आधारित बिजली संयंत्रों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया. परंतु देश में अगले 200 वर्षों तक के लिए कोयले का विशाल भंडार मौजूद है. फिर भी आज देश को अरबों डॉलर चुका कर मजबूरन कोयला आयात करना पड़ रहा है. क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? गैस बिजली संयंत्र बंद पड़ गए हैं. देश में गैस भंडार है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ाया जा रहा है. मजबूरन हमें ज्यादा गैस आयात करनी पड़ रही है.

सीए सुनील गोयल

आज देश में इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल, हार्डवेयर, फर्नीचर, टाइल्स से लेकर गारमेंट तक तमाम दैनिक खपत की वस्तुएं भारी मात्रा में आयात हो रही हैं. भारत सॉफ्टवेयर में लीडर बन सकता है तो हार्डवेयर में क्यों नहीं? लेकिन सरकार की नीतियां ही सही नहीं है. ना ही इसकी चिंता दिखाई पड़ती है. सरकार ने टेलिकॉम क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया, परंतु टेलिकॉम-हार्डवेयर उपकरणों के देश में ही उत्पादन का कोई प्रयास नहीं हुआ. नतीजतन आज देश में अरबों डॉलर मूल्य का हार्डवेयर आयात हो रहा है. यही नहीं भारत मिनरल्स का निर्यात तो बढ़ा रही है, परंतु उसके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात बढ़ाने का प्रयास नहीं है. सरकार आज केवल गोल्ड आयात घटाने की कोशिश में जुटी है. यह दर्शाया जा रहा है कि सारी समस्या की जड़ गोल्ड का ज्यादा आयात है. गोल्ड इम्पोर्ट घट जाएगा तो सारा संकट दूर हो जाएगा. जबकि ऐसा नहीं है. देश को गुमराह किया जा रहा है.

सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि गोल्ड के प्रति आकर्षण सदियों से रहा है और रहेगा. यह कितना भी महंगा हो जाए. इसकी मांग नहीं घटेगी. क्योंकि यह एक तरह से दुनिया की सबसे सुरक्षित 'मुद्रा' है. फिर भी सरकार गोल्ड के अलावा पेट्रोलियम-गैस, कोयला, मोबाइल-हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक या अन्य कोई वस्तु का आयात घटाने का कोई प्रयास नहीं कर रही है. जिन पर गोल्ड से काफी ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है. इसके कारण देश के घरेलू उद्योग संकट में आ रहे हैं.

'मुफ्तखोरी' का बोझ 3 करोड़ करदाताओं पर

पर लगता है कि सरकार मौजूदा आर्थिक संकट के प्रति गंभीर नहीं है. तभी तो वह मनरेगा के बाद अब खाद्य सुरक्षा विधेयक जैसी वोट बटोरू और देश का घाटा और बढ़ाने जैसी योजनाएं ही ला रही हैं. सरकार ने खाद्य सुरक्षा तो लागू कर दी, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का कोई उपाय नहीं. तो क्या खाद्य जरूरत आयात से पूर्ति की जाएगी? आज हर कोई राजनैतिक दल 'मुफ्त' बांटकर वोट जुटाने के चक्कर में है. क्या यह देश हित में है? आज देश की आबादी 125 करोड़ है और उसमें से मात्र 3 करोड़ लोग टैक्स अदा करते हैं. अर्थात जो टैक्स दे रहा है, उसे और दबाया जाए. उस पर और टैक्स बोझ डाला जाए. उससे वसूल कर बाकी सब को 'मुफ्त' बांटा जाए. यानी जो काम कर रहा है, उससे वसूला जाए और जो काम नहीं कर रहा है, उसे 'मुफ्त' देकर और कामचोर बनाया जाए. यह कैसा विकास है? 'मुफ्तखोरी' की बजाय सबको रोजगार देने के लिए योजनाएं लानी चाहिए. जिससे समाज के हर वर्ग और पूरे देश का सही ढंग से विकास हो सकेगा. क्या इसके लिए ईमानदार पहल होगी?

यदि सरकार सचमुच आर्थिक संकट को दूर करने के प्रति गंभीर है तो उसे सभी वस्तुओं का आयात घटाने की कोशिश कर देश के विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र पर फोकस करना चाहिए. जिससे देश का सही तरीके से विकास होकर रोजगार अवसरों में वृद्धि हो सकेगी.

(लेखक लैडरअप कार्पोरेट एडवायजरी के प्रबंध निदेशक हैं)